IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 5, July 2026
Impact Factor: 8.2

भारत की विदेश नीति में परिवर्तन :2014 से 2024 तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण

राजकुमारी पटेल[1] **एवं** डॉ. दीपक[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग

[2] सह-प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग

विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र

सारांश

2014 से 2024 के बीच भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले, जिनमें रणनीतिक स्वायत्तता, पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय जुड़ाव, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भूमिका, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी, रूस के साथ पारंपरिक संबंधों का संरक्षण, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा एवं संवाद, तथा वैश्विक दक्षिण में भारत की सक्रिय भूमिका प्रमुख रही। इस अवधि में विदेश नीति को केवल पारंपरिक कूटनीतिक संबंधों तक सीमित न रखकर आर्थिक, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, समुद्री सहयोग, प्रवासी भारतीयों और बहुपक्षीय संस्थाओं से जोड़ा गया। 2014 में 'लुक ईस्ट' नीति को 'एक्ट ईस्ट' नीति में परिवर्तित किया गया, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक एवं रणनीतिक संबंधों को अधिक सक्रिय स्वरूप मिला।

इसी अवधि में ''पड़ोसी पहले' के माध्यम से दक्षिण एशियाई पड़ोस में संपर्क, व्यापार और जन-से-जन संबंधों को प्राथमिकता दी गई। भारत की विदेश नीति में अमेरिका के साथ रक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ा, जबकि रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंधों को बनाए रखते हुए भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को जारी रखा। चीन के साथ सीमा विवाद और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा ने भारत की सुरक्षा एवं हिंद-प्रशांत रणनीति को प्रभावित किया। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के सामने पश्चिमी देशों, रूस और वैश्विक दक्षिण के बीच अपने हितों का संतुलन बनाए रखने की चुनौती और अधिक स्पष्ट हुई।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

मुख्य शब्द: भारत की विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, रणनीतिक स्वायत्तता, एक्ट ईस्ट नीति, पड़ोसी प्रथम नीति, हिंद-प्रशांत, भारत-अमेरिका संबंध, भारत-रूस संबंध, भारत-चीन संबंध, वैश्विक दक्षिण।

प्रस्तावना

भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, संप्रभुता, क्षेत्रीय स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मूल उद्देश्यों पर आधारित रही है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन के साथ इसकी प्राथमिकताओं और कूटनीतिक साधनों में समय-समय पर बदलाव आया है। 2014 से 2024 का दशक इस दृष्टि से विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस अवधि में भारत ने एक ओर पारंपरिक रणनीतिक साझेदारियों को बनाए रखा, वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को व्यापक बनाया।

इस दशक में भारत की विदेश नीति को अधिक सक्रिय, बहु-आयामी और हित-आधारित स्वरूप प्राप्त हुआ। विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और प्रवासी भारतीयों की भूमिका भी अधिक महत्वपूर्ण हुई। इसलिए 2014–2024 को समझने के लिए केवल सरकार परिवर्तन को आधार बनाना पर्याप्त नहीं है; बल्कि चीन के उदय, अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, रूस-पश्चिम तनाव, हिंद-प्रशांत की बढ़ती रणनीतिक महत्ता और वैश्विक शक्ति-संतुलन में बदलाव जैसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय कारकों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

2014 के बाद विदेश नीति की प्रमुख दिशा

2014 के बाद भारत की विदेश नीति में पड़ोस और विस्तारित पड़ोस दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया। "पड़ोसी पहले' नीति के माध्यम से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ संपर्क, व्यापार, डिजिटल एवं भौतिक कनेक्टिविटी तथा जन-से-जन संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसी प्रकार 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' ने दक्षिण-पूर्व एशिया को भारत की आर्थिक और रणनीतिक नीति में अधिक प्रमुख स्थान दिया। भारत सरकार के अनुसार यह नीति मूलतः आर्थिक पहल से आगे बढ़कर राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयामों तक विस्तारित हुई। इस नीति के अंतर्गत आसियान देशों, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों में विविधता आई। इससे

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

भारत की विदेश नीति का भौगोलिक दायरा भी विस्तृत हुआ और हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत की रणनीतिक सोच का प्रमुख हिस्सा बन गया।

हिंद-प्रशांत और क्वाड की भूमिका

2014–2024 के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम बनकर उभरा। भारत ने समुद्री सुरक्षा, स्वतंत्र एवं खुला समुद्री क्षेत्र, संपर्क, आपदा राहत और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर अधिक सक्रिय भूमिका अपनाई। शोध के अनुसार चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते शक्ति-संतुलन ने भारत को हिंद-प्रशांत अवधारणा को अपनी रणनीतिक सोच में अधिक महत्व देने के लिए प्रेरित किया।

इसी संदर्भ में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड सहयोग का महत्व बढ़ा। हालांकि, भारत ने इसे औपचारिक सैन्य गठबंधन के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय व्यापक क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन और सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित सहयोग के मंच के रूप में आगे बढ़ाया। यह परिवर्तन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए विभिन्न शक्तियों के साथ सहयोग बढ़ाने की नीति को दर्शाता है।

भारत-अमेरिका संबंधों में परिवर्तन

2014–2024 के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग का विस्तार हुआ। दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा तथा चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण रहा। अमेरिका के साथ बढ़ती निकटता के बावजूद भारत ने औपचारिक सैन्य गठबंधन की नीति नहीं अपनाई और रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को भी जारी रखा। इस प्रकार भारत की नीति को रणनीतिक साझेदारियों के विविधीकरण के रूप में देखा जा सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत की विदेश नीति में पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षा साझेदारी बढ़ना इस दशक के महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों में से एक था।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

भारत-रूस संबंध और रणनीतिक स्वायत्तता

रूस भारत की विदेश नीति में लंबे समय से रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। 2014–2024 के दौरान अमेरिका के साथ भारत की निकटता बढ़ने के बावजूद रूस के साथ रक्षा संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह संतुलन और महत्वपूर्ण हो गया। भारत ने संघर्ष के संदर्भ में संवाद और कूटनीति पर जोर दिया तथा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रूस के साथ ऊर्जा और अन्य आर्थिक संबंध बनाए रखे। इस परिस्थिति ने भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय विमर्श में फिर से प्रमुख बनाया। इस नीति का मूल तत्व किसी एक शक्ति-गुट पर पूर्ण निर्भरता के बजाय विभिन्न देशों के साथ मुद्दा-आधारित सहयोग बनाए रखना रहा।

भारत-चीन संबंध

भारत-चीन संबंध 2014–2024 के दशक में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों से प्रभावित रहे। व्यापार और बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसर बने रहे, लेकिन सीमा विवाद और सुरक्षा संबंधी तनावों ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया। विशेष रूप से 2020 के बाद सीमा पर तनाव ने भारत की सुरक्षा नीति तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारियों को अतिरिक्त महत्व दिया। इसी कारण भारत ने एक ओर चीन के साथ संवाद के चैनल बनाए रखने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को भी बढ़ाया। इस द्वंद्व से स्पष्ट होता है कि भारत की चीन नीति केवल प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहीं थी, बल्कि प्रतिस्पर्धा, संवाद और राष्ट्रीय हितों के संतुलन का मिश्रण रही।

वैश्विक दक्षिण और बहुपक्षीय कूटनीति

2014–2024 में भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ अपनी भूमिका को अधिक सक्रिय रूप से प्रस्तुत किया। जी20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत ने विकास, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और विकासशील देशों की चिंताओं को उठाया। 2023 में जी20 की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताएँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इस दौरान भारत की विदेश नीति में बहुपक्षीय संस्थाओं के उपयोग का

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

विस्तार दिखाई दिया। यह नीति भारत को एक साथ विकसित और विकासशील दोनों समूहों के साथ संवाद करने की सुविधा देती रही।

विदेश नीति में आर्थिक और तकनीकी आयाम

इस दशक में विदेश नीति और आर्थिक नीति के बीच संबंध भी अधिक स्पष्ट हुआ। व्यापार, विदेशी निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति-श्रृंखला, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ विदेश नीति के महत्वपूर्ण विषय बने। भारत ने अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम एशियाई देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को विस्तार दिया। इसके साथ ही भारत ने ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण रूस तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंधों को भी महत्व दिया। इस प्रकार आर्थिक सुरक्षा धीरे-धीरे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा बनती गई।

पश्चिम एशिया और समुद्री क्षेत्र

भारत के लिए पश्चिम एशिया ऊर्जा, व्यापार, प्रवासी भारतीयों और समुद्री संपर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। 2014–2024 में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल और अन्य पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों में विविधता आई। भारत ने पश्चिम एशिया में विभिन्न देशों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखा, जबकि क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री संपर्क और सुरक्षा सहयोग भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इस प्रकार भारत की विदेश नीति का दायरा दक्षिण एशिया से आगे बढ़कर पश्चिम एशिया, अफ्रीका और हिंद-प्रशांत तक अधिक व्यापक हुआ।

तुलनात्मक सारणी

विदेश नीति क्षेत्र 2014 से पहले प्रमुख रुझान 2014–2024 प्रमुख परिवर्तन प्रमुख समाचार/चुनाव	पड़ोसी देश पारंपरिक दक्षिण एशियाई पासपोर्ट पड़ोस प्रथम पर जोर से संपर्क बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान एवं कुछ पड़ोसियों को चुने जाने में	दक्षिण-पूर्व एशिया पूर्व की ओर देखो नीति अधिनियम पूर्व की नीति राजवंश एवं अर्थव्यवस्था में विस्तार	हिंद-प्रशांत अल्पमत मजहबी सिद्धांत सक्रिय इंडो-पैसिफिक जुड़ाव समुद्री सहयोग और उद्योग की भूमिका भव्य

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

अमेरिका नामांकित एवं संचालित का यूक्रेनी विकास रक्षा, प्रौद्योगिकी नामांकित का विस्तार चीन-रूस आपूर्ति के साथ संतुलन की आवश्यकता	रूस पारंपरिक रक्षा संबद्ध संबंध जारी, साथ में पश्चिम से जापानी स्वामित्व की परीक्षा	चीन आर्थिक सहयोग और सीमा विवाद दोनों अधिक स्पष्ट राष्ट्रमंडल सीमा तनाव और व्यापार अवलोकन	वैश्विक दक्षिण पूर्वी देशों के साथ पारंपरिक सहयोग को अधिक सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका के लिए मंच प्रदान करने का प्रयास
बहुसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय में निर्णायक	आर्थिक निवेश, व्यापार एवं निवेश केंद्र, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आपूर्ति-श्रृंखला और निवेश पर अधिक जोर आर्थिक सुरक्षा का बढ़ना महत्वपूर्ण है	समुद्री नीति हिंद महासागर पर मुख्य ध्यान हिंद-प्रशांत तक अध्ययन दृष्टिकोण समुद्री सुरक्षा एवं संपर्क की प्रमुख भूमिका	
विदेश नीति क्षेत्र 2014 से पहले प्रमुख रुझान 2014–2024 प्रमुख परिवर्तन प्रमुख समाचार/चुनाव	पड़ोसी देश पारंपरिक दक्षिण एशियाई पासपोर्ट पड़ोस प्रथम पर जोर से संपर्क बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान एवं कुछ पड़ोसियों को चुने जाने में	दक्षिण-पूर्व एशिया पूर्व की ओर देखो नीति अधिनियम पूर्व की नीति राजवंश एवं अर्थव्यवस्था में विस्तार	हिंद-प्रशांत अल्पमत मजहबी सिद्धांत सक्रिय इंडो-पैसिफिक जुड़ाव समुद्री सहयोग और उद्योग की भूमिका भव्य
अमेरिका नामांकित एवं संचालित का यूक्रेनी विकास रक्षा, प्रौद्योगिकी नामांकित का विस्तार चीन-रूस आपूर्ति के साथ संतुलन की आवश्यकता	रूस पारंपरिक रक्षा संबद्ध संबंध जारी, साथ में पश्चिम से जापानी स्वामित्व की परीक्षा	चीन आर्थिक सहयोग और सीमा विवाद दोनों अधिक स्पष्ट राष्ट्रमंडल सीमा तनाव और व्यापार अवलोकन	वैश्विक दक्षिण पूर्वी देशों के साथ पारंपरिक सहयोग को अधिक सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका के लिए मंच प्रदान करने का प्रयास
बहुसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय में निर्णायक	आर्थिक निवेश, व्यापार एवं निवेश केंद्र, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आपूर्ति-श्रृंखला और निवेश पर अधिक जोर आर्थिक सुरक्षा का बढ़ना महत्वपूर्ण है	समुद्री नीति हिंद महासागर पर मुख्य ध्यान हिंद-प्रशांत तक अध्ययन दृष्टिकोण समुद्री सुरक्षा एवं संपर्क की प्रमुख भूमिका	
विदेश नीति क्षेत्र 2014 से पहले प्रमुख रुझान 2014–2024 प्रमुख परिवर्तन प्रमुख समाचार/चुनाव	पड़ोसी देश पारंपरिक दक्षिण एशियाई पासपोर्ट पड़ोस प्रथम पर जोर से संपर्क बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान एवं कुछ पड़ोसियों को चुने जाने में	दक्षिण-पूर्व एशिया पूर्व की ओर देखो नीति अधिनियम पूर्व की नीति राजवंश एवं अर्थव्यवस्था में विस्तार	हिंद-प्रशांत अल्पमत मजहबी सिद्धांत सक्रिय इंडो-पैसिफिक जुड़ाव समुद्री सहयोग और उद्योग की भूमिका भव्य

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

अमेरिका नामांकित एवं संचालित का यूक्रेनी विकास रक्षा, प्रौद्योगिकी नामांकित का विस्तार चीन-रूस आपूर्ति के साथ संतुलन की आवश्यकता	रूस पारंपरिक रक्षा संबद्ध संबंध जारी, साथ में पश्चिम से जापानी स्वामित्व की परीक्षा	चीन आर्थिक सहयोग और सीमा विवाद दोनों अधिक स्पष्ट राष्ट्रमंडल सीमा तनाव और व्यापार अवलोकन	वैश्विक दक्षिण पूर्वी देशों के साथ पारंपरिक सहयोग को अधिक सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका के लिए मंच प्रदान करने का प्रयास
बहुसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय में निर्णायक	आर्थिक निवेश, व्यापार एवं निवेश केंद्र, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आपूर्ति-श्रृंखला और निवेश पर अधिक जोर आर्थिक सुरक्षा का बढ़ना महत्वपूर्ण है	समुद्री नीति हिंद महासागर पर मुख्य ध्यान हिंद-प्रशांत तक अध्ययन दृष्टिकोण समुद्री सुरक्षा एवं संपर्क की प्रमुख भूमिका	
विदेश नीति क्षेत्र 2014 से पहले प्रमुख रुझान 2014–2024 प्रमुख परिवर्तन प्रमुख समाचार/चुनाव	पड़ोसी देश पारंपरिक दक्षिण एशियाई पासपोर्ट पड़ोस प्रथम पर जोर से संपर्क बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान एवं कुछ पड़ोसियों को चुने जाने में	दक्षिण-पूर्व एशिया पूर्व की ओर देखो नीति अधिनियम पूर्व की नीति राजवंश एवं अर्थव्यवस्था में विस्तार	हिंद-प्रशांत अल्पमत मजहबी सिद्धांत सक्रिय इंडो-पैसिफिक जुड़ाव समुद्री सहयोग और उद्योग की भूमिका भव्य
अमेरिका नामांकित एवं संचालित का यूक्रेनी विकास रक्षा, प्रौद्योगिकी नामांकित का विस्तार चीन-रूस आपूर्ति के साथ संतुलन की आवश्यकता	रूस पारंपरिक रक्षा संबद्ध संबंध जारी, साथ में पश्चिम से जापानी स्वामित्व की परीक्षा	चीन आर्थिक सहयोग और सीमा विवाद दोनों अधिक स्पष्ट राष्ट्रमंडल सीमा तनाव और व्यापार अवलोकन	वैश्विक दक्षिण पूर्वी देशों के साथ पारंपरिक सहयोग को अधिक सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका के लिए मंच प्रदान करने का प्रयास

तालिका में उल्लिखित 'एक्ट ईस्ट' और 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीतिगत रूपरेखा भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में भी स्पष्ट की गई है।

समीक्षा से उभरते प्रमुख निष्कर्ष

उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि 2014–2024 के दौरान भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन को केवल नेतृत्व परिवर्तन का परिणाम मानना पर्याप्त नहीं है। एक ओर भारत ने विदेश नीति को अधिक सक्रिय, बहु-क्षेत्रीय और रणनीतिक बनाया, वहीं दूसरी ओर कई नीतिगत आधार पूर्ववर्ती दशकों से विकसित हो रहे थे। कुछ अध्ययनों में 2014 के बाद बड़े संरचनात्मक परिवर्तन, विशेषकर हिंद-प्रशांत, पश्चिमी सुरक्षा साझेदारियों

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

और बहुपक्षीय संस्थाओं में सक्रियता को रेखांकित किया गया है। दूसरी ओर हालिया अकादमिक विश्लेषण यह तर्क देता है कि अमेरिका, रूस और चीन के संदर्भ में भारत की रणनीतिक गणनाओं में महत्वपूर्ण निरंतरता भी रही तथा 2014 को पूर्णतः निर्णायक मोड़ मानना उचित नहीं होगा। इसलिए साहित्य में 'परिवर्तन बनाम निरंतरता' दोनों दृष्टिकोण मौजूद हैं।

निष्कर्ष

2014 से 2024 तक भारत की विदेश नीति ने पारंपरिक गैर-संप्रदाय की विरासत को पूरी तरह से छोड़ देने के बजाय उसे राजवंशीयता और बहु-साझेदारी के नए संदर्भ में पुनर्गठित किया। इस अवधि में नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, इंडो-पैसिफिक, क्वाड, ग्लोबल साउथ और इकोनॉमिक-तकनीकी नामांकन जैसे आयाम अधिक प्रमुख हैं। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ सहयोग को मजबूत किया, रूस के साथ पारंपरिक सहयोग कायम किया और चीन के साथ सहयोग और संवाद जारी रखा।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी में विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक आयामों को शामिल किया गया। समग्र साहित्य यह संकेत देता है कि 2014-2024 के दशक में भारतीय विदेश नीति में पूर्ण परिवर्तन की तुलना में नामांकन, पिरामिड पुनर्संतुलन और नए बहुआयामी अवसरों के विस्तार का काल था। इस अवधि में भारत ने विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपना स्वत्व-निर्णय-क्षमता कायम करते हुए अनेक शक्ति-केंद्रों के साथ संबंध विकसित करने का प्रयास किया।

संदर्भ

1. आर्याल, एस. के., और भारती, एस. एस. (2023). आज़ादी के बाद से 'भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' का विकास। सोसाइटी, 60, 224–232.
2. बाजपेयी, सी. (2022). नई शक्ति-राजनीति के दौर में भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को फिर से मज़बूत करना। द पैसिफिक रिव्यू, 36(3), 631–661.
3. हॉल, आई. (2019). मोदी और भारतीय विदेश नीति का नया रूप। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. लैडविग, डब्ल्यू. सी. (2024). भारतीय विदेश नीति में इंडो-पैसिफिक। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज़ इंस्टीट्यूट।
5. चौधरी, आर. (2022). भारत की आर्थिक कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी। इंटरनेशनल अफेयर्स, 98(3), 865–882.

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 5, July 2026
Impact Factor: 8.2

6. पाठक, एम. (2026). 2014 से 2024 तक भारत की विदेश नीति के रुझान, चुनौतियाँ और अवसर। इफिसियों -इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस।